Need to take comprehensive measures to address the problems arising out of natural calamities in Uttarakhand

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (हरिद्वार) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य में बार-बार आने वाली बाढ़ की गंभीर और आवर्ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मैं इस सदन से तत्काल ध्यान की मांग करता है । हाल ही में जुलाई और अगस्त, 2024 में आई बाढ़ ने अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डाला है । 1 अगस्त, 2024 को भारी वर्षा के कारण घरों के ढहने और बाढ़ से छह लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए ।

हरिद्वार, टिहरी, देहरादून और चमोली जिलों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव देखा गया । हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गईं, सूखी नदी उफान पर आ गई, जिससे अनेक वाहन बह गए । भूपतवाला, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में कालोनियों और बाजारों में पानी भर गया । खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा ।

गंगा और सोलानी नदियों से आई बाढ़ ने विशेष रूप से किसानों को भारी नुकसान पहुँचाया है । इन नदियों में अचानक छोड़े गए पानी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गईं, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है । रिपोर्टों के मुताबिक 53,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है ।

यह बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है । कृषि और स्थानीय व्यवसायों पर इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है ।

मेरी सरकार से प्रमुख मांग है कि गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदी के किनारे बैरिकेडिंग और तटबंध निर्माण करवाये जाएं । ये बैरिकेड्स और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं, जिससे लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है । हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, इसलिए उसको किया जाए ।

बांधों से पानी छोड़ने की जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, उसी को अपनाया जाए । एक वैज्ञानिक और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाकर धीरे-धीरे पानी छोड़ा जाए, ताकि बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सके ।

बाढ़ से प्रभावित किसानों को समय पर और उचित मुआवजा दिया जाए । फसल नुकसान का आंकलन करके उचित मुआवजा तय किया जाए । मुआवजे की राशि के लिए एक अवधि तय की जाए, यह अवधि तीन महीने की होनी चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति संभल सके ।

नदी के मार्ग की सफाई और मार्ग का विस्तार किया जाए । गंगा और सोलानी नदियों के जलमार्ग की सफाई की जाए और इनकी गहराई बढ़ाई जाए ताकि अधिक पानी को धारण किया जा सके और बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सके ।

सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से नदी में गिरने वाले रासायनिक कचड़े पर रोक लगाई जाए ताकि भूमि की उर्वरता बची रहे ।

समुदाय-आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए । स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं । प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए जाएं और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जाए ।

माननीय महोदया, उत्तराखंड के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि बाढ़ के प्रभावों को कम करने और राज्य के लिए एक अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं और गंगा के तटबंधों को मजबूत किये जाएं ताकि किसानों को, विशेष रूप से गन्ना किसानों को जो इस सीज़न में भारी नुकसान होता है, उससे बचा जा सके ।

धन्यवाद ।